नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 087
दि. 29.12.2025,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

महाराष्ट्र निकाय चुनाव: गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर सियासी पेंच ने बढ़ाई हलचल, कई महानगरपालिकाओं में रणनीति अभी अधूरी

(जीएनएस)। मुंबई। महाराष्ट्र में आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव और अन्य प्रमुख नगरपालिकाओं के चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं। अमरावती, नासिक, मालेगांव, धुले, नागपुर, सोलापुर, जलगांव, छत्रपती संभाजीनगर और केडीएमसी सहित राज्य की कई नगरपालिकाओं में गठबंधन, सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन को लेकर पार्टियों के बीच चल रही सियासी जद्दोजहद ने स्थिति को बेहद जटिल बना दिया है। चुनावी तैयारियों की शुरुआत से ही सभी दल अपने उम्मीदवारों और गठबंधनों को लेकर सतर्क हैं, लेकिन अंतिम निर्णय अभी भी कई स्थानों पर लंबित है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन निकाय चुनावों के परिणाम राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

अमरावती महानगरपालिका में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट (UBT) के बीच गठबंधन की चर्चाएं तेज हैं। रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील देशमुख और ठाकरे गुट के जिला प्रमुख पराग गुडधे के बीच हुई बैठक में आगामी रणनीति पर विचार किया गया। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि सोमवार शाम तक इस गठबंधन की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। अमरावती की राजनीतिक स्थिति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह नगरपालिका क्षेत्र बीजेपी और महाविकास आघाड़ी (MVA) के लिए सेंसेटिव माना जाता है। अमरावती में गठबंधन के पीछे मुख्य उद्देश्य है—भाजपा के प्रभाव को चुनौती देना और

स्थानीय मतदाताओं के बीच संतुलन स्थापित करना।

नासिक में महायुति के अंदर सीट बंटवारे को लेकर मतभेद जारी हैं। कुल 122 सीटों में बीजेपी 85 सीटों की मांग पर अड़ी है, जबकि शिंदे गुट 45 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) 30 सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहा है। इस क्षेत्र में राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए शीर्ष नेतृत्व ही अंतिम निर्णय लेगा। स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुसार, यदि सीट बंटवारा सही ढंग से नहीं हुआ तो महायुति गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

मालेगांव और धुले जैसी नगरपालिकाओं में भी चुनावी प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। मालेगांव में गठबंधन को लेकर स्पष्टता न होने के कारण उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि दस्तावेज सत्यापन में सतर्कता बरत रहे हैं। वहीं धुले में भी नामांकन की अंतिम तारीख नजदीक आने के बावजूद उम्मीदवार सावधानीपूर्वक अपने दस्तावेज जमा कर रहे हैं। यह स्थिति संकेत देती है कि दोनों नगरपालिकाओं में राजनीतिक दल अपने गठबंधन और सीट बंटवारे की रणनीति पर अंतिम निर्णय लेने से पहले हर पहलू का अध्ययन कर रहे हैं। सोलापुर और छत्रपती संभाजीनगर में गठबंधन को लेकर रणनीति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। सोलापुर महानगरपालिका में शिंदे गुट और अजित पवार गुट ने मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है और दोनों ने 5151 सीटों का फॉर्मूला तय किया है। वहीं छत्रपती संभाजीनगर में बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन पर अंतिम फैसला अभी लंबित है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इन क्षेत्रों में गठबंधन की मजबूती और सीट बंटवारे के फैसले निकाय चुनावों के नतीजों को सीधे प्रभावित करेंगे।

बीजेपी कार्यकर्ताओं में कई क्षेत्रों में नाराजगी देखने को मिली है। केडीएमसी और कल्याण-डोंबिवली में पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से काम करने के बावजूद उनके साथ अन्याय हुआ है। उनका मानना है कि यदि गठबंधन करना ही है, तो सीट बंटवारा निष्पक्ष रूप से 50-50 होना चाहिए। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की यह नाराजगी चुनावी रणनीति में चुनौती उत्पन्न कर सकती है, जिससे गठबंधन के अंदर संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाएगा।

शरद पवार गुट (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) ने भी सोलापुर महानगरपालिका चुनाव के लिए उम्मीदवार सूची जारी की है। इस सूची में 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे के तहत सोलापुर में कुल 20 सीटें शरद पवार गुट को मिली हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम गठबंधन में संतुलन बनाए रखने और स्थानीय मतदाताओं में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

राज्य में आगामी निकाय चुनावों में गठबंधन, सीट बंटवारा और उम्मीदवार चयन को लेकर चल रही इस जटिल राजनीति ने चुनावी रणनीति को बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया है। राजनीतिक दल स्थानीय समीकरणों, जातीय और भाषा आधारित वोट बैंक, और गठबंधन की मजबूती को ध्यान में रखकर अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया में जुटे हैं। इन निकाय चुनावों के परिणाम न केवल नगरपालिकाओं के प्रशासनिक ढांचे को प्रभावित करेंगे, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा और आगामी विधानसभा चुनावों के समीकरणों पर भी असर डालेंगे।

मनरेगा में बदलाव पर आम आदमी पार्टी का बड़ा हमला, केंद्र पर गरीबों का हक छीनने का आरोप

(जीएनएस)। अमृतसर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा में किए गए बदलावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक और पंजाब इकाई के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि मनरेगा के स्वरूप में बदलाव कर गरीब मजदूरों की रोजी-रोटी पर सीधा वार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह योजना देश के करोड़ों ग्रामीण गरीबों के लिए जीवनरेखा है और इसमें छेड़छाड़ कर केंद्र सरकार गरीब विरोधी सोच को उजागर कर रही है।

कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार को तुरंत तथाकथित 'वीबी-जी राम-जी बिल' को वापस लेना चाहिए और वर्ष 2005 में बने मूल मनरेगा कानून को पूरी तरह लागू करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि नए बदलावों के जरिए केंद्र सरकार ने मनरेगा की शत-प्रतिशत फंडिंग से खुद को अलग कर लिया है और अब 40 प्रतिशत आर्थिक बोझ राज्यों पर डाल दिया गया है। धालीवाल ने कहा कि पहले यह योजना पूरी तरह केंद्र प्रायोजित थी, जिससे राज्यों को मजदूरों को काम देने में किसी तरह की वित्तीय दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब 60-40 के फंडिंग मॉडल ने राज्यों की कमर तोड़ दी है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्यों की जीएसटी का बड़ा हिस्सा पहले ही केंद्र सरकार के पास चला जाता है, तो राज्य सरकारें यह अतिरिक्त 40 प्रतिशत रकम आखिर कहां से लाएंगी। धालीवाल ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए कहा कि केंद्र एक ओर राज्यों के संसाधन अपने पास रखता है और दूसरी ओर गरीबों की योजनाओं का बोझ भी उन्हीं राज्यों पर डाल रहा है। उनके अनुसार इसका सीधा असर ग्रामीण इलाकों में काम और मजदूरी पर पड़ेगा।

आप नेता ने नए नियमों के तहत कृषि बिजाई और कटाई के मौसम में मनरेगा का काम बंद किए जाने पर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जिन गरीब मजदूरों के पास अपनी जमीन तक नहीं है, जो दो मरले गेहूं भी नहीं बोते, वे इन महीनों में क्या खाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले मजदूरों को साल में 100 दिन काम की गारंटी थी और वे अपनी जरूरत के हिसाब से काम चुन सकते थे, लेकिन अब यह गारंटी भी धीरे-धीरे खत्म की जा रही है। धालीवाल ने इसे ग्रामीण गरीबों के साथ अन्याय करार दिया।

कुलदीप सिंह धालीवाल ने भाजपा पर अमीरों के पक्ष में और गरीबों के खिलाफ नीतियां बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार की हर नीति बड़े उद्योगपतियों और धनाढ्य वर्ग को फायदा पहुंचाने वाली रही है। उन्होंने पंजाब में हाल की बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ रुपये की मदद की घोषणा तो की, लेकिन आज तक एक रुपया भी जारी नहीं किया गया। इसके अलावा ग्रामीण विकास से जुड़े कई फंड भी लगातार रोके जा रहे हैं, जिससे गांवों में विकास कार्य ठप होते जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मनरेगा कोई खैरात नहीं है, बल्कि यह वही पैसा है जो राज्यों से जीएसटी के रूप में लिया जाता है और बाद में गरीबों के रोजगार के लिए लौटाया जाना चाहिए। लेकिन अब केंद्र सरकार उसी पैसे को रोककर पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों के अधिकारों पर सीधा हमला कर रही है। धालीवाल के अनुसार पहले गांवों में सड़क, तालाब, नाली, पंचायत भवन जैसे कई विकास कार्य मनरेगा के तहत होते थे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता था, लेकिन नए बदलावों से यह पूरा तंत्र कमजोर किया जा रहा है।

आप प्रवक्ता ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने मनरेगा में किए गए बदलाव तुरंत वापस नहीं लिए, तो आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी सड़क से लेकर संसद तक गरीबों और मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ेगी। धालीवाल ने पंजाब के मजदूरों और ग्रामीण गरीबों को भरोसा दिलाया कि आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर उनका रोजगार और अधिकार छिनने नहीं देगी और मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश का डटकर विरोध किया जाएगा।

सीमा पार नशे और आतंक के गठजोड़ पर निर्णायक प्रहार की तैयारी जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तेज की जमीनी और खुफिया कार्रवाई

(जीएनएस)। जम्मू। जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से संचालित नशीले पदार्थों की तस्करी और उससे जुड़े आतंकी नेटवर्क पर अब निर्णायक शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इस चुनौती से निपटने के लिए एक नई, व्यापक और सख्त रणनीति तैयार की है, जिसका मकसद केवल तस्करों को पकड़ना ही नहीं, बल्कि पूरे उस इकोसिस्टम को ध्वस्त करना है, जो नशे की कमाई से आतंकवाद को जीवनदान देता है। राजौरी–पुंछ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल तजिंदर सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब सुरक्षा एजेंसियों की प्राथमिकता सीमा पार नशा तस्करी और आतंक के गठजोड़ को जड़ से खत्म करने की होगी, इसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी जमीनी खुफिया तंत्र को पहले से कहीं अधिक मजबूत और सक्रिय किया जाएगा। पुंछ जिले में आयोजित इंटेलिजेंस, सुरक्षा और अपराध समीक्षा बैठक के दौरान DIG तजिंदर सिंह ने अधिकारियों और फील्ड कमांडरों को साफ निर्देश दिए कि पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ इनोवेटिव और आधुनिक इंटेलिजेंस संग्रह तकनीकों को अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय तस्कर गिरोह और आतंकी समर्थक नेटवर्क अक्सर

स्थानीय परिस्थितियों, सामाजिक रिश्तों और भौगोलिक जटिलताओं का फायदा उठाते हैं, इसलिए इन्हें बेनकाब करने के लिए स्थानीय स्तर पर भरोसेमंद सूचना तंत्र सबसे अहम हथियार है। DIG ने यह भी दोहराया कि केवल तकनीकी निगरानी पर निर्भर रहने के बजाय, बीट स्तर पर काम कर रहे पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच संवाद को और मजबूत किया जाना चाहिए। बैठक में इस बात पर खास जोर दिया गया कि बीट सिस्टम को पूरी सख्ती और ईमानदारी से लागू किया जाए। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने इलाकों में नियमित बीट चेक सुनिश्चित करें और हर संदिग्ध गतिविधि, व्यक्ति या नेटवर्क की जानकारी को व्यवस्थित तरीके से दर्ज करें। DIG तजिंदर सिंह ने कहा कि आतंकी इकोसिस्टम को समर्थन देने वाले तत्व, नशा तस्करी से जुड़े नेटवर्क, भगोड़े अपराधी और इलाके में डर या अस्थिरता फैलाने वाले असामाजिक तत्व, इन सभी की पहचान और निरंतर निगरानी पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान पुंछ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शफकत हुसैन ने जिले की मौजूदा सुरक्षा और इंटेलिजेंस स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों, चौकियों और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कैंपों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही फील्ड इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने के लिए स्थानीय स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को तेज किया गया है। अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि हाल के वर्षों में नशा तस्करी के पैटर्न में बदलाव आया है और तस्कर नए-नए रास्तों और तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पुलिस को भी रणनीति में लगातार बदलाव करना पड़ रहा है।

बैठक में यह भी सामने आया कि नशीले पदार्थों की तस्करी केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधा जुड़ा मुद्दा बन चुकी है। नशे से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को फंड करने, स्थानीय युवाओं को गुमराह करने और सीमावर्ती इलाकों में अस्थिरता फैलाने के लिए किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अब तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क को चिन्हित कर एक साथ कार्रवाई करने की रणनीति अपनाने का फैसला किया है, ताकि छोटे स्तर के तस्करों के साथ-साथ उनके आकाओं तक भी पहुंचा जा सके।

समीक्षा बैठक के बाद DIG तजिंदर सिंह और SSP शफकत हुसैन ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक स्थित किर्नी और कस्बा गांवों का दौरा भी किया। इस दौरान दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों ने सुरक्षा, आवाजाही और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कुछ चिंताएं साझा कीं, जिन पर अधिकारियों ने गंभीरता से ध्यान देने और त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। DIG ने ग्रामीणों से कहा कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में स्थानीय लोगों की भूमिका बेहद अहम है और पुलिस उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार है।

उन्नाव कांड में न्याय की लड़ाई फिर सड़कों पर, जंतर-मंतर पर उबाल, कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ प्रदर्शन में टकराव

(जीएनएस)। नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस एक बार फिर देश की राजनीति, न्याय व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर बहस के केंद्र में आ गया है। पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा निलंबित कर सशर्त जमानत दिए जाने के फैसले के विरोध में रविवार को राजधानी के जंतर-मंतर पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। महिला अधिकार संगठनों, वामपंथी छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर इस फैसले को पीड़िता के लिए अन्याय बताते हुए केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जिस मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था, उसमें दोषी को राहत देना न्याय के मूल सिद्धांतों पर सवाल खड़ा करता है।

प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय और तनावपूर्ण हो गया जब कुलदीप सेंगर के समर्थन में एक महिला 'आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर' लिखा पोस्टर लेकर जंतर-मंतर पहुंच गई। इस दृश्य को देखते ही प्रदर्शनकारियों में आक्रोश फैल गया। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में धक्का-मुक्की और झड़प की स्थिति में बदलने लगी। मौके पर तैनात पुलिस बल ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला और बड़े टकराव को टलने से रोका। हालांकि इस घटना ने प्रदर्शन में मौजूद लोगों की नाराजगी और गुस्से को और बढ़ा दिया।

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी गई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं और वही पीड़िता को वास्तविक न्याय दिला सकता है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर न्याय की मांग की और कहा कि दोषियों को राहत देना महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देने जैसा है।

उन्नाव रेप पीड़िता ने आजतक से बातचीत में जमानत के आदेश को अपने और अपने परिवार के लिए 'काल' करार दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जमानत के आदेश ने सेंगर की सजा को रोक दिया है और उसके परिवार के लोग जेल में उससे लगातार मिल रहे हैं। उसने कहा कि उसे और उसके परिवार को मारने के लिए एक करोड़ रुपये की सुपारी दी गई थी और अब जमानत के बाद खतरा और बढ़ गया है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि जज और सीबीआई के जांच अधिकारी बिक चुके हैं। साथ ही उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।

पीड़िता की मां बातचीत के दौरान भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि उनका परिवार पिछले कई वर्षों से न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति को मार दिया गया और अब उन्हें हाई कोर्ट पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। पीड़िता की मां ने कहा कि अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही उन्हें उम्मीद है। उन्होंने यह भी दावा किया कि परिवार को मिली सुरक्षा हटा ली गई है और कुलदीप सेंगर उन्हें मरवाने की कोशिश कर रहा है।

प्रदर्शन में शामिल सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने कहा कि एक बार फिर पीड़िता को सड़क पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश की महिलाएं आहत हैं और यह संदेश जा रहा है कि रसूखदार लोग सजा के बावजूद राहत पा सकते हैं। उनके अनुसार अब न्याय की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही है। उल्लेखनीय है कि उन्नाव रेप केस साल 2017 में सामने आया था, जब एक नाबालिग लड़की ने तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया था। शुरुआत में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में टालमटोल की और पीड़िता के परिवार को लगातार धमकियां दी गईं। 2018 में पीड़िता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया, जिसके बाद मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केस सीबीआई को सौंपा गया और सुनवाई के लिए दिल्ली स्थानांतरित किया गया। साल 2019 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत और गवाहों को प्रभावित करने के मामलों में भी सेंगर को दोषी ठहराया गया।

हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की अपील लंबित रहने तक सजा निलंबित करते हुए सशर्त जमानत दी। कोर्ट ने शर्त रखी कि सेंगर पीड़िता के निवास स्थान के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएंगे और किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। हालांकि पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में मिली 10 साल की सजा के चलते सेंगर फिलहाल जेल में ही हैं। इसके बावजूद जमानत के फैसले ने एक बार फिर उन्नाव कांड की पीड़ा को ताजा कर दिया है और सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या पीड़ितों को सच में न्याय मिल पा रहा है या नहीं।

संपादकीय

आतंक और अपराध की जुगलबंदी पर निर्णायक प्रहार का समय

दिल्ली में आयोजित आतंकवाद रोधी सम्मेलन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा संगठित अपराध तंत्र के खिलाफ जिस समेकित डाटाबेस का लोकार्पण किया गया, वह देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम माना जाना चाहिए। बदलते समय के साथ अपराध और आतंकवाद का स्वरूप भी बदलता गया है। अब ये दोनों अलग-अलग ध्रुव नहीं रह गए हैं, बल्कि कई मामलों में एक-दूसरे के पूरक बनते जा रहे हैं। इसी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा तैयार किया गया यह डाटाबेस समय की आवश्यकता के अनुरूप है और यह संकेत देता है कि सुरक्षा एजेंसियां अब केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि पूर्व-नियोजित और समन्वित रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं।

इस डाटाबेस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें देशभर में सक्रिय आतंकी संगठनों, संगठित अपराध गिरोहों, कुख्यात गैंगस्टरों, उनके नेटवर्क, आपसी संपर्कों और गतिविधियों से जुड़ी सूचनाओं को एक मंच पर समाहित किया गया है। इसके साथ ही गुम और बरामद हथियारों, उनकी तस्करी के मार्गों और इस्तेमाल के पैटर्न का भी विवरण शामिल किया गया है। यह तथ्य अब किसी से छिपा नहीं रहा कि सीमा पार से आने वाले हथियार और मादक पदार्थ न केवल आतंकियों तक पहुंच रहे हैं, बल्कि बड़े अपराधी गिरोहों के लिए भी ताकत का स्रोत बनते जा रहे हैं। इन हथियारों और पैसों के सहारे अपराधी अपने नेटवर्क को मजबूत करते हैं और आतंकी संगठन अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि आतंकवादी गतिविधियों के पीछे स्थानीय स्तर पर अपराधियों का सहयोग अहम भूमिका निभाता है। किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए जमीन पर मदद, ठिकाने, फर्जी दस्तावेज, हथियारों की आपूर्ति और आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। यह सब बिना संगठित अपराध तंत्र के सहयोग के संभव नहीं हो पाता। यही कारण है कि अब आतंकवाद और संगठित अपराध को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साझा चुनौती के रूप में देखने की जरूरत है। एनआईए द्वारा तैयार यह डाटाबेस इसी सोच को व्यवहार में उतारने का प्रयास है।

इस डाटाबेस को सभी राज्यों की पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा, जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान तेज और सटीक हो सकेगा। अब तक अक्सर देखा गया है कि सूचनाएं अलग-अलग एजेंसियों में बिखरी रहती थीं, जिससे समय रहते कार्रवाई नहीं हो पाती थी। यदि यह डाटाबेस वास्तव में सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया गया और इसे लगातार अपडेट किया जाता रहा, तो यह आतंकवाद और संगठित अपराध दोनों के खिलाफ लड़ाई में एक प्रभावी हथियार साबित हो सकता है। हालांकि इसके साथ यह भी उतना ही जरूरी है कि इस प्रणाली का उपयोग केवल औपचारिकता तक सीमित न रह जाए, बल्कि जमीनी स्तर पर इसके ठोस परिणाम दिखाई दें। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केवल सीमा पर सख्ती या मुठभेड़ों से काम नहीं चलता। इसके लिए उस पूरे तंत्र को तोड़ना जरूरी है, जो पर्दे के पीछे से आतंक को जीवन देता है। इसमें फंडिंग नेटवर्क, हवाला, मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों की अवैध सप्लाई शामिल है। संगठित अपराध के गिरोह इन सभी गतिविधियों में गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि इन गिरोहों की कमर तोड़ी जाती है, तो आतंकवाद की रीढ़ भी कमजोर पड़ेगी। इस दृष्टि से यह डाटाबेस एक साझा मोर्चा तैयार करने का माध्यम बन सकता है। एक गंभीर सवाल यह भी है कि कई बड़े अपराधी जेल में बंद रहने के बावजूद अपने नेटवर्क को संचालित करते रहते हैं। यह स्थिति न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि आम नागरिकों के विश्वास को भी कमजोर करती है। जेलों के भीतर से अपराध का संचालन आखिर कैसे और क्यों हो रहा है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। जेल प्रशासन, पुलिस और अन्य संबंधित संस्थाओं की जवाबदेही तय किए बिना संगठित अपराध पर पूरी तरह लगाम लगाना संभव नहीं होगा। इस दिशा में भी केंद्र और राज्य सरकारों को ठोस और कठोर कदम उठाने की जरूरत है। यह सही है कि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। कई आतंकी नेटवर्क ध्वस्त हुए हैं और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ में भी कमी आई है।

असामान्य ठंड से निपटने को जरूरी कारगर रणनीति

> दक्षिण भारत में ठंड के मौसम में उत्तरी हवाओं के असामान्य रूप से गहरे प्रवेश के कारण आंतरिक हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट आयी। जिसका गंभीर असर पारिस्थितिकी व मानव जीवन पर हो रहा है। इसमें जलवायु बदलाव की बड़ी भूमिका है।

कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ में कभी स्वेटर की दुकान नहीं होती थी, आज वहां लोग रूम हीटर खरीद रहे हैं। यह हाल भीषण गर्मी के लिए मशहूर पूरे उत्तरी-कर्नाटक का है। धारवाड़ में तापमान लगातार 10.2 डिग्री के आसपास है। इसी तरह, गदग में न्यूनतम तापमान 10.8, बीदर में 10 डिग्री सेल्सियस, हासन में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हासन, विजयपुर के बाजारों में पहली बार जाड़े के कपड़ों की बिक्री जमकर हो रही है। बेंगलुरु में इतनी सर्दी कभी देखी नहीं गई। उधर चेन्नई में सालों बाद 20 डिग्री से नीचे तापमान गया और समुद्र किनारे के इस महानगर के लिए यह कड़ाके की ठंड बन गया। ऊटी तो खैर राज्य का पहाड़ी क्षेत्र है लेकिन वहां भी तापमान 5.3 हो जाना अचरज है। ईरोड के तलवाड़ी में 11.4 डिग्री, डिग्री, धर्मपुरी के कुछ हिस्सों में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यही हाल आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में है। मौसम का बदलता मिजाज समाज, अर्थव्यवस्था आदि पर दूरगामी प्रभाव डालेगा। जलवायु परिवर्तन के लिए सरकार व समाज को चेत जाना चाहिए। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय राज्यों- तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश-तेलंगाना और केरल- को समशीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए जाना जाता है, जहां शीत लहर की स्थिति दुर्लभ होती है। हाल के वर्षों में ठंड के मौसम में उत्तरी हवाओं के असामान्य रूप से गहरे प्रवेश के कारण इन क्षेत्रों के आंतरिक हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अप्रत्याशित शीत लहर के चलते कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री तक नीचे चला गया है। इसका गंभीर असर स्थानीय पारिस्थितिकी प्रणालियों और मानव जीवन पर हो रहा है भारत के 'सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी' का एक शोध बताता है कि साल 2021-2050 के बीच दक्षिण भारत के कई इलाकों का तापमान 0.5 डिग्री से 1.5 डिग्री तक और सर्दियों में न्यूनतम तापमान एक से दो डिग्री तक बढ़ सकता है। यही नहीं खरीफ और रबी दोनों फसली-मौसम में वर्षा में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रिपोर्ट में राज्यों को जलवायु जोखिम मूल्यांकन और लचीली आधारभूत संरचना निर्माण की सलाह दी गई है। बढ़ती मौसम असमानता के कारण बाढ़ के बाद जल-जनित रोग और तापमान उतार-चढ़ाव से श्वसन की समस्याएं बढ़ी हैं। मौसम की ये प्रवृत्तियां दक्षिण भारत के समाज को नई चुनौती है।

दक्षिण भारत की कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसलों पर निर्भर करती है, जो पाले या अत्यधिक ठंड के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। अप्रत्याशित शीत लहर से फसल को नुकसान और उपज में कमी की प्रबल संभावना होती है। दक्षिण भारत, विशेषकर केरल, कर्नाटक के मलनाड आदि पहाड़ी क्षेत्र और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में कॉफी, चाय और इलायची जैसी बागवानी फसलें उगाई जाती हैं, जो ठंड के प्रति संवेदनशील हैं। कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागु तथा केरल व तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान में अचानक गिरावट से पौधों की पत्तियां पाले से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, तापमान कम होने से कॉफी के पौधों में पत्ती झुलसने की समस्या हो जाती है। ठंड की मार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में केले की फसल पर पड़ने की संभावना है। पाला पड़ने पर पत्तियां पीली पड़ जाती हैं व फल छोटे रह जाते हैं। लंबे समय तक ठंड से नारियल व सुपारी के पौधों में विकास रुक जाता है। ऐसा ही असर सब्जी व दालों की खेती पर होगा। कर्नाटक, तमिलनाडु में अचानक शीत लहर के दौरान गायों-भैंसों को बीमारियां तो लगती ही हैं, शरीर का तापमान बनाए रखने को उन्हें अधिक आंतरिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिससे दूध पैदावार में 10-20 फीसदी तक की कमी होती है।

आंध्र प्रदेश, विशेषकर कृष्णा और गोदावरी जिलों में झींगा और मछली पालन होता है। तालाबों में जब पानी का तापमान अचानक गिरता है, तो मछली की चयापचय दर कम हो जाती है, वे भोजन खाना बंद कर देती हैं, और रोगग्रस्त हो जाती हैं। अत्यधिक ठंड में मछलियां मर भी सकती हैं। इसी तरह झींगा फार्मों में पानी का तापमान 20 डिग्री से नीचे जाने पर झींगा का विकास रुक जाता है जिससे किसानों को नुकसान होता है। अचानक जाड़ा पड़ने के साथ ही दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में सांस और खांसी के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। चूंकि उनकी जीवनशैली और आवास हल्के मौसम के अनुरूप बने हैं, अचानक और तीव्र ठंड के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो दक्षिण भारत में पड़ रही अधिक ठंड अल्पकालिक मौसमी विसंगतियों जैसे - ठंडी हवाओं का गहरा प्रवेश, साफ आसमान, चक्रवात के अप्रत्यक्ष असर का परिणाम है। लेकिन, जलवायु परिवर्तन इस संभावना को बढ़ाता है कि शीत लहर जैसी चरम-मौसम की घटनाएं असामान्य रूप से तीव्र या अप्रत्याशित हो सकती हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में जलवायु परिवर्तन न केवल औसत तापमान बढ़ा रहा है, बल्कि मौसमी घटनाओं को चरम और अप्रत्याशित बना रहा है। शीत लहर ने उजागर किया है कि आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्र अब अत्यधिक ठंड के प्रति असुरक्षित हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों में, जहां बुनियादी ढांचा व जीवनशैली गर्मी और आर्द्रता के अनुरूप बनी है, वहां अप्रत्याशित ठंड से निपटने के लिए सरकारों को बहुआयामी और दूरदर्शी रणनीति अपनाने की जरूरत है।

प्रेरणा

जिस दिन मन की मैल दिखी, उसी दिन साधना का द्वार खुला

बहुत पुराने समय की बात है। एक समृद्ध नगर में एक बनिया रहता था। धन, वैभव और व्यापारिक चतुराई में उसकी कोई तुलना नहीं थी। उसकी दुकान पर दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लोग उसे सफल व्यापारी मानते थे, और समाज में उसकी छवि एक धर्मपरायण व्यक्ति की भी थी। वह मंदिरों में दान देता था, साधु-संतों के लिए भोजन की व्यवस्था करता था और पर्व-त्योहारों पर बढ़-चढ़कर पुण्य कर्म करता था। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि उसका जीवन धर्म और धन दोनों से परिपूर्ण है। लेकिन उसके भीतर एक सूक्ष्म आकांक्षा पल रही थी। वह चाहता था कि कोई महान साधु उसे दीक्षा दे दे। उसके मन में यह भाव बैठ गया था कि दीक्षा मिलते ही वह विशेष बन जाएगा, उसका स्थान समाज में और ऊँचा हो जाएगा, और लोग उसे भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में देखने लगेंगे। उसे लगता था कि दीक्षा कोई ऐसी वस्तु है, जो गुरु से मिलते ही हाथ में आ जाती है, जैसे व्यापार में कोई सौदा तय हो जाए।

इसी इच्छा को लेकर वह एक प्रसिद्ध साधु के पास पहुँचा। साधु का जीवन अत्यंत सादा था। वे वर्षों से तपस्या और आत्मसंयम में लीन थे। बनिया ने बड़े आदर से प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साधु ने उसे ध्यान से देखा, जैसे उसकी देह नहीं, उसके भीतर के भावों को पढ़ रहे हों। फिर शांत स्वर में बोले कि अभी नहीं, अगली बार मिलने पर दीक्षा दूँगा। यह उत्तर बनिया को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि उसने तो इतना दान-पुण्य किया है, फिर भी साधु टाल क्यों रहे हैं। इसके बाद वह बार-बार साधु के पास जाने लगा। कभी धन का दान देने की बात करता, कभी महँगे वस्त्र भेंट करता, कभी मीठे शब्दों से साधु को प्रसन्न करने की कोशिश करता। हर बार वही आग्रह करता कि अब तो दीक्षा दे दीजिए। लेकिन साधु का उत्तर नहीं बदलता था। वे हर बार कहते कि अभी समय नहीं आया है।

समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद साधु उसी नगर में फिर आए, लेकिन इस बार उनका रूप अलग था। उनके हाथ में एक भिक्षापात्र था, जो अत्यंत गंदा था। उसमें मिट्टी, बाल, मूत्र और मल जैसी वस्तुएँ पड़ी थीं। साधु सीधे बनिया के द्वार पर पहुँचे और भिक्षा माँगी। जैसे ही बनिया ने साधु को देखा, उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया। उसे लगा कि अब अवश्य उसकी प्रतीक्षा समाप्त होगी। उसने सोचा कि इतने वर्षों बाद साधु स्वयं उसके घर आए हैं, अब तो दीक्षा निश्चित है।

उसने तुरंत घर के भीतर जाकर भव्य तैयारी करवाई। स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई गईं, खीर और हलवा तैयार हुआ, अनेक पकवान सजाए गए। बनिया पूरे मन से सेवा करना चाहता था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में यह आशा भी थी कि आज उसे दीक्षा मिल जाएगी। जब भोजन तैयार हो गया, तो वह आदर के साथ साधु के पास आया।

साधु ने भिक्षापात्र आगे बढ़ाया और कहा कि जो कुछ लाए हो, इसी में डाल दो। बनिया की दृष्टि जैसे ही उस पात्र पर पड़ी, वह ठिठक गया। उसे वह पात्र अत्यंत घृणित लगा। उसने संकोच और असहजता के साथ कहा कि महाराज, मैं इन शुद्ध और स्वादिष्ट पकवानों को इस गंदे पात्र में कैसे डाल सकता हूँ। कृपया पहले इसे साफ कर लें, फिर मैं पूरे सम्मान के साथ सब कुछ इसमें डाल दूँगा।

साधु ने यह सुना और शांत स्वर में कहा कि यदि यह पात्र तुम्हें गंदा लग रहा है, तो जरा अपने हृदय की ओर भी देखो। तुम्हारा मन भी इसी पात्र की तरह भरा हुआ है। उसमें लोभ है, अहंकार है, कामना है, क्रोध है और प्रतिष्ठा की लालसा है। जब यह पात्र इतना अशुद्ध है, तो मैं इसमें ईश्वर का नाम और ब्रह्मज्ञान कैसे डाल दूँ। जिस प्रकार तुम इस पात्र में भोजन डालने से हिचक रहे हो, उसी प्रकार मैं तुम्हारे अशुद्ध मन में दीक्षा कैसे दे सकता हूँ।

ये शब्द बनिया के लिए अत्यंत कठोर थे। उसका चेहरा उतर गया। उसे क्रोध भी आया और लज्जा भी। उसे लगा जैसे साधु ने सबके सामने उसके भीतर की सच्चाई उजागर कर दी हो। बिना कुछ बोले वह वहाँ से चला गया। उस दिन वह बहुत व्यथित रहा। साधु के शब्द उसके मन में बार-बार गूंजते रहे।

धीरे-धीरे उसका क्रोध शांत हुआ और आत्मचिंतन ने स्थान ले लिया। उसने पहली बार ईमानदारी से अपने जीवन को देखा। उसे समझ में आया कि उसका दान भी प्रशंसा की इच्छा से भरा था, उसकी सेवा में भी अहंकार छिपा था और दीक्षा की चाह में भी केवल नाम और सम्मान की भूख थी। यह बोध उसके लिए पीड़ादायक था, लेकिन यही पीड़ा उसके परिवर्तन की शुरुआत बनी।

उसने अब चुपचाप, बिना किसी को बताए, सच्चे मन से दान करना शुरू किया। उसने निस्वार्थ सेवा की, निर्धनों की सहायता की, और अपने व्यवहार में नम्रता लाने का अभ्यास किया। उसने क्रोध और लोभ पर संयम रखने की कोशिश की। धीरे-धीरे उसका मन हल्का होने लगा। अब वह दीक्षा के बारे में नहीं सोचता था। उसे यह समझ में आ गया था कि पहले मन को शुद्ध करना आवश्यक है, फिर ज्ञान अपने-आप उतरता है।

कुछ समय बाद वही साधु फिर नगर में आए। इस बार बनिया उनके पास साधारण भाव से पहुँचा। न कोई दिखावा था, न कोई अपेक्षा। साधु ने उसकी आँखों में देखा और उन्हें वहाँ विनम्रता और शांति दिखाई दी। साधु मुस्कराए और उसे अपने पास बिठाकर दीक्षा दे दी। उस क्षण बनिया की आँखों से आँसू बह निकले। उसने समझ लिया कि दीक्षा कोई वस्तु नहीं, बल्कि पात्रता का फल है।

उस दिन उसे यह सत्य स्पष्ट हो गया कि जब तक मन गंदा है, तब तक ज्ञान नहीं उतरता। जैसे स्वच्छ पात्र में ही अमृत रखा जाता है, वैसे ही शुद्ध हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। उस बनिया का जीवन उसी दिन वास्तव में धर्ममय बना, जिस दिन उसने अपने भीतर की मैल को पहचान लिया और उसे धोने का साहस किया।

बांग्लादेश से सतर्क होने का समय, किसी भी परिस्थिति के लिए रहना होगा तैयार

बांग्लादेश में पिछले वर्ष जुलाई में शेख हसीना सरकार के खिलाफ छेड़े गए छात्र आंदोलन से अशांति और अस्थिरता का जो दौर शुरू हुआ, वह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस आंदोलन के चलते शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा और उन्हें जान बचाने के लिए भारत में शरण लेनी पड़ी। उनके तख्तापलट के बाद सेना के हस्तक्षेप से वहां बनी अंतरिम सरकार की कमान जब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने संभाली तो माना यह गया था कि वे अशांति और अस्थिरता दूर कर वहां बन रहे भारत विरोधी माहौल पर भी लगाम लगाने का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।

16 माह बाद भी बांग्लादेश अशांत एवं अस्थिर है और वहां भारत विरोधी तत्व भी बेलगाम हैं। पिछले दिनों वहां जब एक कट्टरपंथी छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या कर दी गई तो यह अफवाह फैलाई गई कि उसका हत्यारा भारत भाग गया है। उसके साथ-साथ शेख हसीना को भी सौंपने की मांग कर वहां नए सिरे से भारत विरोधी माहौल बनाया जाने लगा। इसी माहौल में वहां एक हिंदू युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई और फिर उसके शव को सबके सामने जला दिया गया। इसके बाद पुलिस ने स्पष्ट किया कि छात्र नेता के हत्यारे के भारत भाग जाने की कहीं कोई सूचना नहीं।

इसके बाद भी वहां भारत विरोधी तत्व उत्पात मचा रहे हैं। वे भारत के उच्चायोग को निशाना बनाने की कोशिश करने के साथ हिंदुओं पर हमले करने में लगे हुए हैं, जबकि हादी के भाई ने उसकी हत्या के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार को ही कठघरे में खड़ा किया है। बीते दिनों वहां एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। इसके अलावा हिंदुओं के घरों में आगजनी की जा रही है। इसी तरह की घटनाएं तब भी हुई थीं, जब शेख हसीना का तख्तापलटा गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच बिगड़ते संबंधों के बीच वहां के सबसे बड़े राजनीतिक दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान जिया का 17 साल बाद लंदन से लौटना एक बड़ा घटनाक्रम है। वह पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान एवं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। इस समय खालिदा जिया गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में हैं। यदि फरवरी में होने वाले आम चुनावों में बीएनपी जीत हासिल करती है तो तारिक रहमान देश की कमान संभाल सकते हैं, लेकिन इन चुनावों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कहना कठिन है।

इसका बड़ा कारण यह है कि अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को प्रतिबंधित कर उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया है। इतना ही नहीं, उस जमाते इस्लामी को चुनाव लड़ने दिया जा रहा है, जिस पर शेख हसीना ने इसलिए प्रतिबंध लगा रखा था, क्योंकि वह पाकिस्तान समर्थक है। जमात ने बांग्लादेश की लड़ाई के समय पाकिस्तान का साथ दिया था। जमाते इस्लामी के साथ ही बांग्लादेश में अन्य ऐसे कट्टरपंथी तत्व बेलगाम हैं, जो भारत विरोध के साथ हिंदुओं पर दमन के लिए कुख्यात हैं। मोहम्मद यूनुस उन पर लगाम लगाने की कहीं कोई कोशिश करते दिख नहीं दिख रहे हैं।

बांग्लादेश का जन्म भारत की मदद से हुआ था। वहां लंबे समय सत्ता में रहीं शेख हसीना भारत की मित्र थीं। उनके समय में दोनों देशों के संबंधों में मजबूती आई, लेकिन अब वहां भारत विरोधी माहौल है। इसका बड़ा कारण मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से भारत विरोधी तत्वों की अनदेखी किया जाना है। वे न तो कट्टरपंथी तत्वों पर लगाम लगाने में दिलचस्पी ले रहे हैं और न ही भारत से संबंध सुधारने में। ऐसा लगता है कि शेख हसीना के प्रति उनकी नाराजगी भारत विरोध में तब्दील हो गई है।

वे भारत की चिंताओं का समाधान करने के बजाय उन्हें बढ़ाने का काम करते दिख रहे हैं। बांग्लादेश को लेकर भारत की चिंता इसलिए और बढ़ गई है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस उस पाकिस्तान से संबंध बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिसने वहां के लोगों पर कहर ढाया था। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि वे भारत को चिढ़ाने के लिए ही पाकिस्तान को अहमियत दे रहे हैं।

बांग्लादेश में केवल पाकिस्तान का ही हस्तक्षेप बढ़ता नहीं दिख रहा, चीन का प्रभाव भी बढ़ रहा है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ चीन को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। उनके रवैए से लगता है भारत से दोस्ती उन्हें पसंद नहीं। भारत से संबंध सुधारने में उनकी अनिच्छा से प्रतीति होती है कि वे बांग्लादेश में भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय ताकतों को भी अवसर दे रहे हैं। ध्यान रहे शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के समय पश्चिमी ताकतों का हाथ देखा गया था। सच जो हो, भारत के लिए यह ठीक नहीं कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के साथ अन्य अंतरराष्ट्रीय ताकतों की भी भूमिका बढ़ती दिख रही है।

भारत को न केवल बांग्लादेश में खतरे का सामना कर रहे हिंदुओं के बारे में सोचना होगा, बल्कि इस देश में अपने हितों की रक्षा के लिए भी कूटनीतिक कौशल दिखाना होगा। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की भूमिका बढ़ने न पाए। भारत को बांग्लादेश के हालात पर गहरी निगाह रखने के साथ वहां चुनाव बाद बनने वाली किसी भी परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा।

कहना कठिन है कि चुनाव में क्या होगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि लोकतंत्र के मामले में बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर जाता हुआ दिख रहा है। जैसे वहां जो सत्ता में आ जाता है, वह अपने राजनीतिक विरोधियों के दमन में जुट जाता है, वैसे ही बांग्लादेश में भी होता है। पिछले चुनाव में शेख हसीना ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी थीं, जिससे खालिदा जिया को चुनावों का बहिष्कार करने के लिए लिए विवश होना पड़ा था।

अब शेख हसीना की पार्टी चाह कर भी चुनाव नहीं लड़ सकती। इन स्थितियों में भारत को बांग्लादेश संबंधी अपनी कूटनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा। वास्तव में बांग्लादेश हो या अन्य कोई देश, भारत को किसी एक पक्ष अथवा राजनीतिक ताकत के प्रति ही निर्भर रहने से बचना होगा। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देना होगा कि उसके पड़ोस में लोकतांत्रिक शक्तियों को बल मिले।

अभियान

जहाँ प्रश्न मौन बन जाता है और सत्य प्रकट होता है

प्राचीन भारत के उस दिव्य कालखंड में, जब ज्ञान केवल शब्दों का संग्रह नहीं था, बल्कि जीवन का अनुभव था, जब गुरु और शिष्य का संबंध केवल शिक्षा तक सीमित न होकर आत्मा से आत्मा का संवाद होता था, उसी समय एक महान ऋषि हुए शौनक। वे अपने युग के अत्यंत प्रतिष्ठित विद्वान थे। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और कर्मकांड का उन्हें गहरा ज्ञान था। यज्ञों की अग्नि उनके आश्रम में निरंतर प्रज्वलित रहती थी, दान-पुण्य से उनका जीवन परिपूर्ण था और समाज उन्हें आदर और श्रद्धा से देखता था। बाहर से उनका जीवन पूर्ण प्रतीत होता था, किंतु भीतर कहीं एक सूक्ष्म रिक्तता थी, एक ऐसा प्रश्न जो न दिन में उन्हें चैन लेने देता था, न रात्रि में।

जब वे एकांत में बैठते, तब उनके भीतर यह विचार उठता कि यदि यह समस्त ज्ञान, यह समस्त कर्म, यह समस्त वैदिक विधियाँ ही अंतिम सत्य हैं, तो फिर मन में यह अधूरापन क्यों है। वे अनुभव करते थे कि यज्ञ समाप्त हो जाते हैं, मंत्रों का उच्चारण मौन में विलीन हो जाता है, दान का फल भी समय के साथ क्षीण हो जाता है। तब उनके हृदय में यह प्रश्न जन्म लेता कि क्या कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, जो नष्ट न होता हो, जो बदलता न हो, जो समय और मृत्यु से परे हो। वह कौन-सा सत्य है, जिसे जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष न रहे।

यही प्रश्न उनके जीवन की दिशा बन गया। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि इस उत्तर की खोज वे किसी ऐसे महापुरुष के पास जाकर करेंगे, जिन्होंने केवल शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, बल्कि सत्य का साक्षात्कार किया हो। इसी संकल्प के साथ वे महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुँचे। अंगिरा उस समय गहन तपस्या में लीन थे। उनके आश्रम में एक अलौकिक शांति थी, मानो वायु भी धीमी गति से चल रही हो। शौनक ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में अपने हृदय का भार उनके सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि भगवन्, मुझे वह बताइए, जिसे जान लेने पर इस जगत की प्रत्येक वस्तु जानी जा सके।

अंगिरा ने शौनक की ओर देखा। उनकी दृष्टि में कोई आश्चर्य नहीं था, बल्कि ऐसी करुणा थी, जैसे वे इस प्रश्न की प्रतीक्षा ही कर रहे हों। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि शौनक, ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक वह, जो संसार को जानने में सहायक होता है, और दूसरा वह, जो स्वयं को जानने का मार्ग खोलता है। उन्होंने बताया कि वेद, वेदांग, यज्ञ, अनुष्ठान और कर्मकांड से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह मनुष्य को जीवन जीने की विधि सिखाता है, समाज को व्यवस्थित करता है, लेकिन आत्मा के रहस्य को प्रकट नहीं करता। यह ज्ञान आवश्यक है, पर अंतिम नहीं।

शौनक ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनके भीतर अब भी जिज्ञासा जीवित थी। तब अंगिरा ने कहा कि वह ज्ञान, जिसके द्वारा उस अविनाशी तत्व का अनुभव होता है, वही परा विद्या है। वही ब्रह्मविद्या है। वह ब्रह्म न जन्म लेता है, न मरता है। वह न आदि है, न अंत। वही इस सृष्टि का मूल कारण है। उसी से यह जगत उत्पन्न हुआ है, उसी में यह स्थित है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। वह इंद्रियों से परे है, फिर भी प्रत्येक कण में विद्यमान है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार अपने-आप मिट जाता है, वैसे ही परा विद्या के उदय से अज्ञान नष्ट हो जाता है। अंगिरा ने शौनक को समझाया कि जिस ब्रह्म को वे बाहर खोज रहे हैं, वह वास्तव में उनके भीतर ही है। जैसे अग्नि लकड़ी में छिपी रहती है और घर्षण से प्रकट होती है, वैसे ही परमात्मा प्रत्येक जीव के भीतर छिपा हुआ है। जब मनुष्य तप, श्रद्धा और संयम के द्वारा अपने मन को शुद्ध करता है, तब वह उस सत्य का साक्षात्कार करता है। यह कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है। यह जान लेने पर मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि तब उसे ज्ञात हो जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप नष्ट होने वाला नहीं है।

इन वचनों को सुनते हुए शौनक का हृदय द्रवित हो उठा। वर्षों से संचित विद्वता का गर्व, पद और प्रतिष्ठा का मोह, सब धीरे-धीरे विलीन होने लगा। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि वे अब तक बाहर की ओर देखते रहे, जबकि सत्य भीतर ही उपस्थित था। अंगिरा ने आगे कहा कि बाहरी संसार सदा परिवर्तनशील है। जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा सदा एक-सी रहती है। जो इस आत्मा को पहचान लेता है, वही वास्तव में अमरत्व को प्राप्त करता है।

अंगिरा ने एक उपमा दी कि जैसे मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है और फिर उसी में निवास करती है, वैसे ही ब्रह्म से यह सृष्टि प्रकट होती है और अंततः उसी में विलीन हो जाती है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष से फिर बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही यह सृष्टि-चक्र ब्रह्म में ही आरंभ और समाप्त होता है। यह जान लेने पर मनुष्य समझ जाता है कि सच्चा यज्ञ बाहरी अग्नि में नहीं, बल्कि भीतर की चेतना को जाग्रत करने में है। सच्चा दान धन का नहीं, अहंकार का त्याग है। और सच्चा ज्ञान स्वयं की पहचान है।

इन शिक्षाओं ने शौनक के जीवन की धारा ही बदल दी। अब वे वही व्यक्ति नहीं थे, जो प्रश्न लेकर आश्रम में आए थे। उनके भीतर एक गहरी शांति उतर चुकी थी। उन्होंने महर्षि अंगिरा को प्रणाम किया और कहा कि आज वे जान गए हैं कि ब्रह्म को कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह सदा से उनके भीतर ही था। अंगिरा ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि जो यह जान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप ही ब्रह्म है, उसके लिए संसार में कोई बंधन शेष नहीं रहता।

मुण्डक उपनिषद का यह संवाद केवल एक कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए एक गहन संदेश है। यह बताता है कि बाहरी ज्ञान हमें संसार में दक्ष बनाता है, लेकिन आंतरिक ज्ञान हमें स्वयं से परिचित कराता है। और जो स्वयं को जान लेता है, वही वास्तव में परम सत्य को जान लेता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

देश में होलिस्टिक व्यू के साथ हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है : केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

-:केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह:-

- विकसित भारत के संकल्प में हेल्दी डेमोग्राफी के लिए चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका
- चिकित्सकों का फोकस इलनेस की बजाय वेलनेस पर होना चाहिए
- देश का स्वास्थ्य बजट वर्ष 2013-14 में 37,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर आज 1,28,000 करोड़ रुपए किया गया
- समय के साथ चिकित्सा क्षेत्र के एथिक्स को रिडिफाइन करना आवश्यक टेलीमेडिसिन तथा वीडियो काउंसलिंग में आईएमए के चिकित्सकों से सहयोग की अपेक्षा

-:मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल:-

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में अद्यतन सुविधाएं, हेल्थकेयर के लिए लेटेस्ट टेक्नॉलोजी तथा अनेक मॉडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सज्ज बनी हैं
- आईएमए नैटकॉन-2025 की थीम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह के 'हेल्थकेयर एंड वेलबीइंग फॉर ऑल' के विचार के अनुरूप है
- इंडियन मेडिकल एसोसिएशन केवल एक व्यावसायिक संगठन नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वास्थ्य संरक्षण का प्लेटफॉर्म बन गया है

(जीएनएस)। गांधीनगर : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में रविवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नव-निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह अहमदाबाद में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शताब्दी के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं दीं और कहा कि देश में होलिस्टिक व्यू के साथ हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वच्छता मिशन, फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, योग दिवस का आयोजन, आयुष्मान भारत योजना, आभा और इंद्रधनुष अभियान, जेनेरिक दवाओं को प्रोत्साहन, साथ

ही टेलीमेडिसिन और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मार्गदर्शन जैसे प्रयास किए गए हैं। उन्होंने जोड़ा कि देश में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1,65,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देश का स्वास्थ्य बजट वर्ष 2013-14 में 37,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर आज 1,28,000 करोड़ रुपए किया गया है, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हेल्दी डेमोग्राफी आवश्यक है और इसमें चिकित्सकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को बीमारी की बजाय वेलनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कोरोना काल में देशभर के चिकित्सकों द्वारा दी गई सेवाओं की हृदय से सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना और जेनेरिक दवाओं के प्रति चिकित्सकों द्वारा सकारात्मक वातावरण तैयार करने की अपेक्षा व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ चिकित्सा क्षेत्र के एथिक्स के मानकों को भी पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी संस्थाओं को मेडिकल एथिक्स को रिडिफाइन करने के प्रयास करने चाहिए। मेडिकल कॉलेजों में भावी डॉक्टरों को एथिक्स की समझ के साथ तैयार कर देश को अच्छे डॉक्टर मिलें, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आईएमए द्वारा की जा रही सेवाकीय गतिविधियों की सराहना की और आईएमए से जुड़े चिकित्सकों से टेलीमेडिसिन तथा वीडियो काउंसलिंग जैसी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि एसोसिएशन चिकित्सकों की मांगों को प्रस्तुत करने के साथ-साथ देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने में भी योगदान देगा।

श्री अमित शाह ने नव-निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल नायक को ऊर्जावान बताते हुए शुभकामनाएं व्यक्त कीं कि उनके नेतृत्व में एसोसिएशन को नई ऊर्जा और गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में स्वास्थ्य क्षेत्र में अद्यतन सुविधाओं, हेल्थकेयर के लिए लेटेस्ट टेक्नॉलोजी तथा अनेक मॉडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुदृढ़ हुई हैं। देश में एम्स, मेडिकल कॉलेजों और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री श्री अमित के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा पर विशेष जोर दिया है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नव-निर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति

आईएमए के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में डॉ. अनिल नायक ने शपथ ग्रहण की

आईएमए द्वारा आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर के पांच हजार से अधिक चिकित्सकों ने भाग लिया

जब श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब राज्य में केवल 1,175 मेडिकल सीटें थीं, जबकि आज जिलेवार मेडिकल कॉलेजों की योजना से हर वर्ष 7000 से अधिक डॉक्टर तैयार हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हुए हैं। वर्ष 2014 से पहले देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, जिनमें 88 प्रतिशत वृद्धि के साथ आज यह संख्या 731 हो गई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जोड़ा कि एमबीबीएस सीटों में 118 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2014 में मेडिकल 51 हजार थी, जो आज बढ़कर एक लाख बारह हजार से पार हो गई हैं। पीजी सीटों में 133 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 हजार से अभी 72 हजार हो गई हैं।

प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने हेतु गुजरात द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात सरकार ने 'विकसित गुजरात @2047' का रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस रोडमैप अंतर्गत वर्ष 2024 तक 100 प्रतिशत यूनिवर्सल हेल्थकेयर कवरेज, एनीमिया और कुपोषण के उन्मूलन जैसे लक्ष्यों के साथ एक स्वस्थ समाज के निर्माण का संकल्प लिया गया है। स्वस्थ और विकसित गुजरात के माध्यम से सशक्त एवं समृद्ध विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मेडिकल क्षेत्र भी अग्रणी भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस वर्ष देशभर में सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती तथा 'वंदे मातरम्' की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के साथ-साथ ऑल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस और एसोसिएशन की शताब्दी भी मनाई जा रही है। ऐसे में यह उत्सव आप सभी के लिए डबल बोनांजा जैसा है। उन्होंने कहा कि एक शताब्दी से भी अधिक समय से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देश के स्वास्थ्य क्षेत्र का मार्गदर्शन कर रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन केवल एक व्यावसायिक संगठन ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वास्थ्य संरक्षण का एक सशक्त मंच बन चुका है।

आईएमए नैटकॉन-2025 की थीम पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन की थीम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के 'हेल्थकेयर एंड वेलबीइंग फॉर ऑल' के विचार के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि 'सर्विस, साइंस और सिनर्जी' की शताब्दी के ध्येय मंत्र के साथ आप सभी एकत्र हुए हैं, यह अभिनंदनीय है। सम्मेलन में होने वाले विचार-विमर्श देश के स्वास्थ्य उपचार क्षेत्र को नई दिशा प्रदान करेंगे।

मुख्यमंत्री ने आईएमए के नए अध्यक्ष डॉ. अनिल नायक और उनकी टीम को शुभकामनाएं दीं तथा आशा व्यक्त की कि नई टीम 'नेशन फर्स्ट, पेशेंट फर्स्ट' के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगी।

इस अवसर पर आईएमए के चीफ पैट्रन और पूर्व अध्यक्ष श्री केतन देसाई ने संस्था की शताब्दी के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह संस्था सम्पूर्णतः लोकतांत्रिक तरीके से और सभी के सहयोग से संचालित होती है। डॉ. देसाई ने देशभर में हेल्थ केयर सेक्टर में हो रहे व्यापक और मूलभूत परिवर्तनों पर प्रकाश डाला। उन्होंने नव-निर्वाचित डॉ. अनिल नायक के संघर्ष की सराहना करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

डॉ. अनिल जे. नायक ने आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की और अपने पहले अध्यक्षीय संबोधन में सभी का आभार व्यक्त करते हुए सरकार के समक्ष अपेक्षाएं रखीं।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के करकमलों द्वारा '100 स्टेप्स फॉर हेल्दी लाइफ' का विमोचन किया गया। साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र भी प्रदान किया गया।

इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिलीप भानुशाली, सेक्रेटरी जनरल सुश्री सर्वरी दत्ता, डॉ. पीयूष जैन, डॉ. अनिल पटेल, डॉ. मेहुल शाह सहित एसोसिएशन के वरिष्ठ पैट्रन्स, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में चिकित्सक उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि आईएमए द्वारा आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर से पांच हजार से अधिक चिकित्सकों ने सहभागिता की।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के करकमलों से 330 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, अनावरण एवं सनद वितरण

(जीएनएस)। गांधीनगर : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के करकमलों से ; मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में रविवार को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा 330 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, ई-लोकार्पण, गणेशजी की मूर्ति का अनावरण तथा नवी वणझर गांव के पुनर्वासित निवासियों को सनद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम अंतर्गत अहमदाबाद शहर के पश्चिम एवं दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वेस्टर्न ट्रंक मेन लाइन प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा "हृदय को आनंद देने वाला यह छोटा, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 1973 की साबरमती बाढ़ त्रासदी में जिन नागरिकों का सब कुछ नष्ट हो गया था, उन्हें आज 50 वर्षों बाद प्लॉट का मालिकाना अधिकार मिला है। इतने बड़े अहमदाबाद शहर में 173 लाभार्थी संख्या में भले ही कम लगें, लेकिन उनके लिए यह क्षण अत्यंत ऐतिहासिक और भावनात्मक है।"

श्री शाह ने इस संवेदनशील निर्णय के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि श्री अमितभाई ठाकर, अहमदाबाद की महापौर तथा म्युनिसिपल कमिश्नर को अभिनंदन दिया। उन्होंने कहा कि पांच दशकों से चली आ रही समस्या का आज स्थायी समाधान हुआ है, जो संवेदनशील शासन का प्रमाण है।

उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम अहमदाबाद के लगभग 15 लाख नागरिकों के लिए पहले गटर के पानी की निकासी की कोई सुगठित व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। वर्ष 2000 से 2005 के दौरान शेला से चांदखेडा तक के क्षेत्रों में तीव्रता से शहरीकरण हुआ, लेकिन संपूर्ण ड्रेनेज व्यवस्था विकसित करने के लिए बड़े बजट और लंबे समय की आवश्यकता थी। कई स्थानों पर गटर ओवरफ्लो की स्थिति देखकर उन्हें सांसद के रूप में पीड़ा होती थी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में अहमदाबाद को आधुनिक ड्रेनेज सुविधा का ऐतिहासिक लाभ

वर्षों पुरानी मांगों का संवेदनशीलता के साथ पूरा होना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्थापित संवेदनशील विकास की राजनीति है : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

वर्ष 2025 अहमदाबाद के लिए विकास की छलांग और विश्व स्तर पर गौरव का वर्ष सिद्ध हुआ है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

उन्होनें आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में लोग अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सकें; ऐसे वातावरण के निर्माण के लिए अमृत योजना सहित शहरी विकास योजनाओं का व्यापक उपयोग किया गया है। लगभग 400 करोड़ रुपए के खर्च से 1200 से 1800 मिली मीटर व्यास की विशाल आरसीसी पाइपलाइनें बिछाई गई हैं। इसके परिणामस्वरूप गोता, चांदलोडिया, साइंस सिटी, साउथ बोपल, भाडज, हेबतपुर, थलतेज, बोपल-घुमा, बोडकदेव, वेजलपुर, सरखेज, मक्तमपुरा, महमदपुरा, फतेहवाडी, शांतिपुरा और सनाथल सहित क्षेत्रों के लगभग 15 लाख नागरिकों को ड्रेनेज ओवरफ्लो और गंदे पानी की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी।

श्री शाह ने कहा, "वर्षों पुरानी मांगों का संवेदनशीलता के साथ समाधान होना; प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्थापित संवेदनशील विकास की राजनीति का परिणाम है। जनता मांग करे या न करे, फिर भी उनकी समस्याओं का समाधान करने की कार्य संस्कृति उन्होंने गुजरात से लेकर समग्र देश में विकसित की है।"

-:मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल:-

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि वर्ष 2025 विदा ले रहा है और यह वर्ष अहमदाबाद के लिए विकास की छलांग तथा विश्व स्तर पर गौरव का वर्ष सिद्ध हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सरकार इस संकल्प के साथ कार्य कर रही है कि सामान्य नागरिकों की रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतें सरलता से पूरी हों। उन्होंने कहा कि आदरणीय मोदी साहब ने हर निर्णय के केंद्र में जनसामान्य नागरिक के हित को रखा है। इसी दृष्टिकोण के कारण नागरिकों के जीवन को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने वाली सुविधाओं में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के प्रयासों से गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र सबसे हरित क्षेत्र बना है। मियावाकी पद्धति से वन एवं ऑक्सीजन पार्क आदि के माध्यम से ग्रीन कवर बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वणझर गांव के नागरिकों को आज सनद प्राप्त हुई है, जो इस विचार को दर्शाती है कि जो लोगों के दुःख को समझे, वही सच्चा लोकसेवक होता है।" शहरी विकास बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत वृद्धि कर 30,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है तथा वर्ष 2025 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आने वाले समय में अहमदाबाद कई अंतरराष्ट्रीय खेलों का केंद्र बनेगा, ऐसे में उन्होंने नागरिकों से शहर को स्वच्छ, सुंदर और हरियाला बनाने का सामूहिक संकल्प लेने का अनुरोध किया।

इस अवसर पर अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन ने शहर के सर्वांगीण शहरी विकास, आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्रीय गृह मंत्री एवं गांधीनगर के सांसद श्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री नरहरि अमीन, स्थानीय विधायक, म्युनिसिपल कमिश्नर श्री बंछानिधि पाणि, कलेक्टर श्री सुजीत कुमार, महानगर पालिका के पदाधिकारी, अधिकारी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

अहमदाबाद मंडल के आदरज मोटी–विजापुर रेलखंड का गेज परिवर्तन कार्य पूर्ण

29 एवं 30 दिसंबर 2025 को 39.75 किमी लंबे ब्रॉड गेज में परिवर्तित इस रेलखंड का सीआरएस पश्चिम सर्कल द्वारा संरक्षा निरीक्षण किया जाएगा

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के अंतर्गत आदरज मोटी–विजापुर रेलखंड (39.75 किमी) का गेज परिवर्तन कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। यह खंड अब मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित होकर आधुनिक, सुरक्षित एवं कुशल रेल परिचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। इस खंड का संरक्षा निरीक्षण (सेफ्टी इंस्पेक्शन) रेल संरक्षा आयुक्त (CRS), पश्चिम सर्कल द्वारा 29 एवं 30 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। आदरज मोटी–विजापुर रेल खंड अहमदाबाद मंडल की आदरज मोटी–विजापुर–अंबलियासन गेज परिवर्तन परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस परियोजना को वर्ष 2022–23 स्वीकृति प्रदान की गई थी। परियोजना की अनुमानित लागत 417.53 करोड़ है, जिसे 17.05.2022 को स्वीकृत किया गया।

इस रेलखंड में कुल 01 मेजर ब्रिज, 44 माइनर ब्रिज तथा 35 रोड अंडर ब्रिज (RUB) का निर्माण किया गया है तथा इस रेलखंड में आदरज मोटी, रांधेजा, उनावा–वासन, मकाखड़, लोदरा एवं विजापुर स्टेशन शामिल हैं।

इस ब्रॉड गेज खंड में 60 किग्रा के नए रेल पैनल बिछाए गए हैं। आदरज मोटी एवं विजापुर स्टेशनों पर स्टैंडर्ड–II इंटरलॉकिंग सिस्टम तथा मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग (MACLS) स्थापित की गई है, जिससे ट्रेनों के परिचालन में संरक्षा, समयपालन और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होगा। गेज परिवर्तन के पश्चात इस मार्ग के माध्यम से यात्रियों को देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों और बड़े शहरों से प्रत्यक्ष ब्रॉड गेज कनेक्टिविटी प्राप्त होगी।

आदरज मोटी वर्तमान में एक विद्यमान द्वि-गेज जंक्शन स्टेशन है, जहाँ से आदरज मोटी–गांधीनगर–अहमदाबाद (ब्रॉड गेज) तथा आदरज मोटी–कड़ी–कटोसन (ब्रॉड गेज) लाइनें जुड़ी हुई हैं। गेज परिवर्तन से पूर्व आदरज मोटी–विजापुर एक पृथक मीटर गेज खंड था, जो अब ब्रॉड गेज में परिवर्तित होकर एकीकृत रेल नेटवर्क का हिस्सा बन गया है।

इस गेज परिवर्तन परियोजना से आदरज मोटी–विजापुर के बीच एकीकृत ब्रॉड गेज रेल प्रणाली उपलब्ध होगी। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी तथा पर्यावरण–अनुकूल, सतत और तेज़ रेल संपर्क सुनिश्चित होगा। बेहतर परिवहन सुविधा से दैनिक यात्रियों, पर्यटकों एवं व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को मजबूती प्राप्त होगी।

संरक्षा निरीक्षण के पूर्ण होने के पश्चात इस मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया जा सकेगा। नए ब्रॉड गेज कनेक्शन से भविष्य में नई यात्री एवं मालगाड़ियों के संचालन की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी। इससे उत्तरी गुजरात के ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, यात्रा समय में कमी आएगी और क्षेत्रीय व्यापार, उद्योग एवं कृषि को नई गति प्राप्त होगी।

समुद्र से आत्मनिर्भरता की ऐतिहासिक शुरुआत, जहाज निर्माण में 44,700 करोड़ के निवेश से भारत बनेगा वैश्विक समुद्री शक्ति

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत के समुद्री भविष्य को नई दिशा देने और जहाज निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। देश के बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने जहाज निर्माण से जुड़ी दो महत्वाकांक्षी योजनाओं के दिशा-निर्देश अधिसूचित करते हुए कुल 44,700 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को मंजूरी दे दी है। यह फैसला न केवल भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूती देगा, बल्कि 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी एक नया आयाम देगा। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक भारत की जहाज निर्माण क्षमता को मौजूदा स्तर से कई गुना बढ़ाकर 4.5 मिलियन ग्रॉस टन प्रति वर्ष तक पहुंचाया जाए, ताकि भारत दुनिया के प्रमुख जहाज निर्माता देशों की कतार में खड़ा हो सके।

केंद्र सरकार की इस नीति का मूल उद्देश्य भारत की घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत करना, विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना और भारतीय शिपयार्ड को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना है। लंबे समय से भारत जहाज निर्माण के क्षेत्र में तकनीकी और वित्तीय चुनौतियों से जूझता रहा है, जिसके कारण बड़े और अत्याधुनिक जहाजों के लिए विदेशी शिपयार्ड पर निर्भरता बनी रही। नई योजनाओं के लागू होने से सरकार को उम्मीद है कि यह स्थिति बदलेगी और भारत न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि वैश्विक मांग को भी पूरा करने की क्षमता विकसित करेगा।

इस नीति के तहत शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम और शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम को लागू किया गया है, जो एक-दूसरे की पूरक हैं। शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के लिए 24,736 करोड़ रुपये का कोष बनाया जाएगा, जिसके तहत भारत में बनाए जाने वाले जहाजों पर सीधे वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार जहाज की श्रेणी और जटिलता के आधार पर 15 से 25 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। छोटे वाणिज्यिक जहाजों से लेकर बड़े कंटेनर जहाजों और विशेष प्रयोजन वाले जहाजों तक के लिए अलग-अलग सहायता दरें तय की गई हैं। यह सहायता चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी, ताकि गुणवत्ता, समयसीमा और तकनीकी मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

दूसरी ओर, शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम के तहत 19,989 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिसका फोकस भविष्य की जरूरतों पर रहेगा। इस योजना के माध्यम से आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास, नई तकनीकों को अपनाना और कुशल मानव संसाधन तैयार करना प्राथमिकता होगी। सरकार का मानना है कि केवल वित्तीय सहायता से ही नहीं, बल्कि तकनीकी नवाचार और प्रशिक्षित कार्यबल के बिना भारत वैश्विक जहाज निर्माण उद्योग में टिकाऊ बढ़त हासिल नहीं कर सकता। इसी सोच के तहत भारतीय शिपयार्ड को आने वाले दशकों की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने की रणनीति बनाई गई है।

सरकार ने जहाज स्क्रैपिंग यानी पुराने जहाजों को तोड़ने और पुनर्चक्रण को भी इस नीति का अहम हिस्सा बनाया है। भारत पहले ही दुनिया के बड़े जहाज स्क्रैपिंग केंद्रों में शामिल है और अब इसे और बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत भारत में जहाज तोड़ने वाले जहाज मालिकों को स्क्रैप मूल्य का 40 प्रतिशत क्रेडिट नोट दिया जाएगा, जिसे नए जहाजों के निर्माण में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे एक ओर पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले जहाजों की संख्या कम होगी, वहीं दूसरी ओर नए जहाजों के निर्माण को गति मिलेगी और सर्कुलर इकॉनमी को मजबूती मिलेगी। सरकारी आकलन के मुताबिक, आने वाले 10 वर्षों में केवल शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के जरिए करीब 96,000 करोड़ रुपये के जहाज निर्माण प्रोजेक्ट्स को समर्थन मिलेगा। इससे न केवल भारी निवेश आएगा, बल्कि समुद्री क्षेत्र से जुड़े हजारों छोटे-बड़े उद्योगों को भी काम मिलेगा। स्टील, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स और डिजाइन जैसे सहायक क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अनुमान है कि इस पूरी प्रक्रिया से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे तटीय राज्यों की अर्थव्यवस्था को विशेष लाभ होगा।

नई नीति के तहत ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जहां अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ जहाज निर्माण किया जा सकेगा। इन क्लस्टरों के लिए साझा बुनियादी ढांचे पर सरकार 100 प्रतिशत पूंजी सहायता देगी, ताकि निजी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। इसके साथ ही मौजूदा शिपयार्ड के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए भी 25 प्रतिशत तक पूंजी सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का मानना है कि पुराने शिपयार्ड को आधुनिक तकनीक से लैस करना उतना ही जरूरी है जितना नए क्लस्टर विकसित करना। इसके अलावा, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। यह केंद्र रिसर्च, डिजाइन, नवाचार और स्किल डेवलपमेंट का राष्ट्रीय हब बनेगा। यहां आधुनिक जहाज डिजाइन, ग्रीन शिप टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और डिजिटल शिपबिल्डिंग जैसे क्षेत्रों पर काम किया जाएगा। इससे भारत न केवल जहाज निर्माण में बल्कि समुद्री तकनीक के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन सकेगा। कुल मिलाकर, जहाज निर्माण में 44,700 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का यह फैसला भारत के समुद्री इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। यह नीति आने वाले वर्षों में भारत को एक मजबूत समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने की नींव रखती है। 2047 तक निर्माण क्षमता को 4.5 मिलियन ग्रॉस टन तक ले जाने का लक्ष्य केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस सपने का प्रतीक है, जिसमें भारत अपने समुद्र, अपने उद्योग और अपनी तकनीक के दम पर वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ खड़ा नजर आएगा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जीवनचरित्र पर आधारित मेगा म्यूजिकल मल्टीमीडिया शो 'नमोत्सव' कार्यक्रम का उद्घाटन किया

- नमोत्सव किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास की यात्रा है : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह
- अहमदाबाद में 150 कलाकारों द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जीवन, विचार और राष्ट्रनिर्माण की यात्रा को नमोत्सव के माध्यम से प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत किया गया
- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी एवं मंत्रियों की प्रोत्साहक उपस्थिति

(जीएनएस)। गांधीनगर : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जीवन, विचार, कार्य संस्कृति और राष्ट्र के प्रति अडिग संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित मेगा म्यूजिकल मल्टीमीडिया शो 'नमोत्सव' केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास, संकल्प और संस्कारों की यात्रा है।

रविवार को अहमदाबाद के संस्कारधाम, घुमा में आयोजित प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जीवनचरित्र पर आधारित मेगा म्यूजिकल मल्टीमीडिया शो 'नमोत्सव' कार्यक्रम में प्रसिद्ध कलाकार श्री साईराम दवे सहित कुल 150 कलाकारों ने भाग लिया। जिसे केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, उपमुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, मंत्रियों सहित सभी उपस्थित महानुभावों ने रुचिपूर्वक देखा।

श्री शाह ने कहा कि नमोत्सव के माध्यम से ऐसे जीवन का प्रस्तुतीकरण होता है, जिसने केवल 11 वर्षों की अल्प अवधि में 140 करोड़ भारतीयों के मन में यह दृढ़ विश्वास स्थापित किया है कि भारत विश्व में प्रथम बनेगा। यह विश्वास विचारों, कार्यों, योजना और अडिग संकल्प से जन्म लेता है, और यह तभी संभव होता है जब कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन उस विचार के लिए समर्पित कर दे।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कोई सामान्य नेता नहीं हैं, बल्कि अपनी नियति को अपनी नीयत से गढ़ने वाले असाधारण व्यक्तित्व हैं। अनेक नेता परिस्थितियों के कारण ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, लेकिन नरेन्द्र मोदी ऐसे एकमात्र नेता हैं जिन्होंने निष्ठा, पारदर्शिता और राष्ट्रहित की भावना से सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि अत्यंत गरीब परिवार में जन्म लेकर जीवन की शुरुआत करने वाले नरेन्द्र मोदीजी आज ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें विश्व के 29 देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का गौरव है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में 11 वर्षों में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज सुरक्षा मिली, 11 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन, 15 करोड़ से अधिक शौचालय, 10 करोड़ से अधिक घरों में शुद्ध पेयजल, 56 करोड़ लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया और 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के मकान मिले हैं। उन्होंने बल देकर कहा कि अपने लिए एक कमरा भी न बनवाने वाले प्रधानमंत्री ने करोड़ों गरीबों को घर बनाकर दिए हैं। यही नीति, नीयत और नेतृत्व का श्रेष्ठ उदाहरण है।

श्री अमित शाह ने कहा कि अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी ने ज्योतिग्राम योजना के माध्यम से राज्य के प्रत्येक गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचाई और गुजरात को विकास का मॉडल बनाया। यही कार्य संस्कृति आज पूरे भारत के लिए प्रेरणा बन गई है। उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 का अंत, आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, भारत का चौथा और तेजी से तीसरा सबसे बड़ा अर्थतंत्र बनना, डिजिटल व्यवस्था में विश्व में प्रथम स्थान ; ये सभी उपलब्धियां दृढ़ नीयत और स्पष्ट दृष्टि का परिणाम हैं।

श्री शाह ने कहा कि नमोत्सव नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। देश के बच्चों, युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए यह कार्यक्रम जीवन में मूल्यों, देशप्रेम और सेवा-भावना को जागृत करेगा।

अंत में श्री अमित शाह ने संस्कारधाम के आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि तीन दिनों तक समाज के सभी वर्गों को नमोत्सव देखने का अवसर दिया गया, इसके लिए संस्कारधाम अभिनंदन के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि नमोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि नरेन्द्र मोदी द्वारा भारत के लिए स्थापित किए गए मानकों को आत्मसात करने की यात्रा है।

'नमोत्सव' कार्यक्रम को देखने के लिए आईसीसी के चेयरमैन श्री जय शाह, मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल, राज्य मंत्री श्रीमती रिवाबा जाडेजा, श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, राज्यसभा सांसद श्री परिमल नथवाणी, भाजपा शहर अध्यक्ष श्री प्रेरकभाई शाह, संस्कारधाम के चेयरमैन डॉ. आर. के. शाह, राजनीतिक एवं सामाजिक अग्रणी तथा बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित रहे।

चीन की सेना में भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार, शी जिनपिंग के आदेश पर तीन शीर्ष सैन्य अधिकारी पद से हटाए गए, सत्ता और सैन्य ढांचे में मचा भूचाल

(जीएनएस)। बीजिंग। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चल रहा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार कार्रवाई देश की सैन्य व्यवस्था के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बीच चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार ने तीन बेहद वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया है। यह फैसला चीनी संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति की बैठक में लिया गया, जहां सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और उससे जुड़े अहम पदों पर बैठे अधिकारियों को निष्कासित करने का निर्णय हुआ। हटाए गए अधिकारियों में वांग रेनहुआ, झांग होंगबिंग और वांग पेंग शामिल हैं, जो सेना और सुरक्षा तंत्र में बेहद प्रभावशाली माने जाते थे।

इस कार्रवाई को राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उस सख्त नीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वे सेना को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखने और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या सत्ता के समानांतर केंद्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। शी जिनपिंग लंबे समय से यह कहते आए हैं कि सेना की "राजनीतिक शुद्धता" और "पूर्ण निष्ठा" देश की सुरक्षा के लिए सबसे अहम है। ऐसे में शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर कार्रवाई यह साफ संकेत देती है कि अब भ्रष्टाचार के आरोपों में कोई भी पद या रुतबा ढाल नहीं बन सकता।

वांग रेनहुआ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की राजनीतिक और कानूनी मामलों की समिति के प्रमुख थे और सेना के भीतर अनुशासन, सैन्य अदालतों और जेलों की व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। उन्हें पिछले साल ही शी जिनपिंग ने एडमिरल के पद पर प्रमोट किया था, जिससे उनकी ताकत और प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे पहले वे गोबी रेगिस्तान स्थित जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में राजनीतिक इकाई के प्रमुख रह चुके थे और 2017 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के ईस्ट सी फ्लीट में एंटी-करप्शन अधिकारी के तौर पर भी काम कर चुके थे। ऐसे अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप और फिर कार्रवाई, चीन के सैन्य तंत्र के भीतर गहरी जड़ों तक फैली समस्या की ओर इशारा करती है।

झांग होंगबिंग, जिन्हें 2022 में फुल जनरल के पद पर प्रमोट किया गया था, पीपुल्स आर्म्ड पुलिस के राजनीतिक कमिश्नर थे। यह बल चीन में आंतरिक सुरक्षा, दंगों और संवेदनशील अभियानों में अहम भूमिका निभाता है। झांग इससे पहले पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के ईस्टर्न थिएटर कमांड में राजनीतिक कमिश्नर रह चुके हैं, जो ताइवान से जुड़े सैन्य अभियानों और रणनीतिक तैयारियों में बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में उनका पद से हटाया जाना न सिर्फ सैन्य बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बड़ा घटनाक्रम है। तीसरे अधिकारी वांग पेंग, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के ट्रेनिंग और प्रशासन विभाग के निदेशक थे। वे सेना के प्रशिक्षण ढांचे और प्रशासनिक नीतियों की निगरानी करते थे। वांग पेंग को दिसंबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया था। उन्होंने नानजिंग यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की थी और इसके बाद सेना में कई अहम जिम्मेदारियां संभालीं। वे ईस्टर्न थिएटर कमांड में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में शिक्षा निदेशक और उपाध्यक्ष भी रहे। ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई यह दिखाती है कि शी जिनपिंग केवल लड़ाकू या ऑपरेशनल यूनिट्स ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षण और प्रशासन जैसे अहम क्षेत्रों को भी पूरी तरह साफ करना चाहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये तीनों अधिकारी पिछले कई महीनों से सार्वजनिक कार्यक्रमों से गायब थे। जुलाई के अंत में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना की सालगिरह और अक्टूबर में कम्युनिस्ट पार्टी के चौथे प्लेनम सत्र में उनकी गैरमौजूदगी ने पहले ही अटकलों को जन्म दे दिया था। अब आधिकारिक तौर पर उनके पद से हटाए जाने से यह साफ हो गया है कि उनके खिलाफ जांच चल रही थी और उसे शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी मिली हुई थी।

हालांकि, इन अधिकारियों को अभी कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी से नहीं हटाया गया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ वक्त की बात हो सकती है। चीन में आमतौर पर पहले पद से हटाया जाता है और बाद में पार्टी की सदस्यता पर फैसला होता है। शी जिनपिंग के पिछले अभियानों को देखें तो कई बड़े नेता और जनरल पहले इसी प्रक्रिया से गुजर चुके हैं।

इस बीच, चीनी एयरफोर्स के दो और शीर्ष अधिकारियों को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। एयर फोर्स कमांडर चांग डिंगकिउ और पॉलिटिकल कमिश्नर गुओ पुशियाओ 24 दिसंबर को राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी वाले एक अहम कार्यक्रम में नजर नहीं आए। चीन की राजनीतिक व्यवस्था में किसी बड़े कार्यक्रम से किसी वरिष्ठ अधिकारी की गैरहाजिरी को अक्सर आने वाली कार्रवाई का संकेत माना जाता है। इससे यह संभावना और मजबूत हो गई है कि शी जिनपिंग का एंटी-करप्शन अभियान अभी और तेज हो सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभियान केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि सेना के भीतर पूर्ण निष्ठा सुनिश्चित करने की रणनीति भी है। ताइवान, दक्षिण चीन सागर और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच शी जिनपिंग चाहते हैं कि सेना पूरी तरह उनके नियंत्रण में रहे और किसी भी स्तर पर अविश्वास या अंदरूनी गुटबाजी की गुंजाइश न बचे। ऐसे में शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर यह कार्रवाई चीन की राजनीति और सुरक्षा नीति दोनों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है।

कोल इंडिया के पुनर्गठन की बड़ी पहल, 2030 तक सभी अनुषंगी कंपनियां उतरेंगी शेयर बाजार में

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सरकारी क्षेत्र की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के ढांचे और कामकाज में बड़ा बदलाव आने वाला है। केंद्र सरकार ने कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की तैयारी तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर कोयला मंत्रालय ने इस संबंध में एक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसके तहत वर्ष 2030 तक कोल इंडिया की सभी सहायक इकाइयों को आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में लाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस पहल को कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

कोल इंडिया लिमिटेड देश के कुल घरेलू कोयला उत्पादन का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अकेले संभालती है और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में इसकी अनुषंगी कंपनियों की लिस्टिंग को केवल एक वित्तीय फैसला नहीं, बल्कि ऊर्जा और सार्वजनिक क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि अलग-अलग सहायक कंपनियों के शेयर बाजार में आने से उनके संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी, बोर्ड और प्रबंधन की जवाबदेही तय होगी और निवेशकों को भी सीधे तौर पर इन कंपनियों की कार्यप्रणाली में भागीदारी का अवसर मिलेगा।

वर्तमान में कोल इंडिया आठ अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से देशभर में कोयला उत्पादन, खनन योजना, डिजाइन और संबंधित गतिविधियों का संचालन करती है। इनमें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड शामिल हैं। अभी तक ये सभी कंपनियां कोल इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाइयों के रूप में काम कर रही हैं, लेकिन लिस्टिंग के बाद इनकी अलग पहचान और बाजार में स्वतंत्र वैल्यू तय होगी। सूत्रों के अनुसार सरकार इस पूरी प्रक्रिया को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहती है, ताकि बाजार पर अनावश्यक दबाव न पड़े और प्रत्येक कंपनी की वित्तीय स्थिति, उत्पादन क्षमता और भविष्य की संभावनाओं के अनुसार सही समय पर लिस्टिंग की जा सके। इसी रणनीति के तहत भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड को पहले चरण में शेयर बाजार में लाने की योजना बनाई गई है। इन दोनों कंपनियों की लिस्टिंग मार्च 2026 तक कराने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कोल इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों में से एक मानी जाती है, जो देश में कोकिंग कोल के उत्पादन और आपूर्ति में प्रमुख भूमिका निभाती है। स्टील उद्योग के लिए कोकिंग कोल की अहमियत को देखते हुए बीसीसीएल की बाजार में अलग पहचान बनाने की संभावना जताई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि बीसीसीएल के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए रोडशो सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं और निवेशकों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी की लिस्टिंग को लेकर बाजार में अच्छा उत्साह है।

इसी तरह सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड कोल इंडिया की तकनीकी रीढ़ मानी जाती है। यह कंपनी खनन योजना, डिजाइन, सर्वेक्षण और तकनीकी सलाह जैसी सेवाएं प्रदान करती है। इसके शेयर बाजार में आने से न केवल कोल सेक्टर बल्कि खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अन्य क्षेत्रों के निवेशकों को भी एक नई विकल्प मिलेगा। सरकार का आकलन है कि सीएमपीडीआई की लिस्टिंग से तकनीकी सेवाओं के क्षेत्र में इसकी क्षमता और विस्तार को नई गति मिलेगी।

सरकार का यह भी मानना है कि अनुषंगी कंपनियों की लिस्टिंग से कोल इंडिया के कुल बाजार मूल्य में भी बढ़ोतरी होगी। अलग-अलग कंपनियों की स्वतंत्र वैल्यू सामने आने से निवेशकों को बेहतर आकलन का मौका मिलेगा और परिसंपत्ति मौद्रिकरण के जरिए सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। साथ ही, सूचीबद्ध होने के बाद इन कंपनियों को पूंजी जुटाने के लिए पूरी तरह से कोल इंडिया या सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे उनके विस्तार और आधुनिकीकरण की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ सकेंगी।

ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि यह कदम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार की दिशा में एक बड़ा संकेत है। आने वाले वर्षों में जब देश की ऊर्जा मांग तेजी से बढ़ेगी और कोयला अभी भी प्रमुख ऊर्जा स्रोत बना रहेगा, ऐसे में कोल इंडिया और उसकी अनुषंगी कंपनियों का मजबूत, पारदर्शी और बाजारोन्मुख होना बेहद जरूरी है। 2030 तक सभी सहायक इकाइयों की लिस्टिंग का लक्ष्य इसी दीर्घकालिक सोच का हिस्सा माना जा रहा है, जो न केवल कोल इंडिया बल्कि पूरे ऊर्जा क्षेत्र के भविष्य को नई दिशा दे सकता है।

टैरिफ की चोट से हिलती अमेरिकी अर्थव्यवस्था, 15 साल में सबसे ज्यादा कंपनियां दिवालिया, ट्रंप के दावों पर गहराता संकट

(जीएनएस)। नई दिल्ली। अमेरिका की आक्रामक टैरिफ नीति, जिसे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्षों तक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने का सबसे कारगर हथियार बताते रहे, अब खुद अमेरिकी कारोबार के लिए गंभीर चुनौती बनती नजर आ रही है। साल 2025 में अमेरिका में कंपनियों के दिवालिया होने के मामलों ने पिछले 15 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है, जब ट्रंप और उनके समर्थक टैरिफ को अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग और राजस्व के लिए वरदान के रूप में पेश करते रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह दिखा रही है कि ऊंचे आयात शुल्क, महंगाई और महंगी कर्ज दरों ने मिलकर अमेरिकी कंपनियों की कमर तोड़ दी है।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों और आर्थिक आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से नवंबर 2025 के बीच अमेरिका में 717 कंपनियों ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब 14 प्रतिशत अधिक है और 2010 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। इन मामलों में चैप्टर 7 और चैप्टर 11 दोनों तरह के दिवालियापन शामिल हैं। चैप्टर 11 के तहत कंपनियां अपने कर्ज का पुनर्गठन कर किसी तरह कारोबार को जारी रखने की कोशिश करती हैं, जबकि चैप्टर 7 का मतलब होता है कंपनी का पूरी तरह बंद हो जाना और उसकी संपत्तियों की बिक्री। विशेषज्ञों का कहना है कि दिवालिया होने वाली कंपनियों की बढ़ती संख्या यह साफ संकेत है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के भीतर गहरे संरचनात्मक दबाव बन चुके हैं।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार, इस संकट की जड़ में ट्रंप प्रशासन की वह टैरिफ नीति है, जिसके तहत चीन समेत कई देशों से आयात होने वाले कच्चे माल और तैयार उत्पादों पर भारी शुल्क लगाए गए। इसका सबसे ज्यादा असर उन अमेरिकी कंपनियों पर पड़ा, जो अपनी सप्लाई चेन के लिए आयात पर निर्भर हैं। दशकों में पहली बार अमेरिकी उद्योगों को इतनी ऊंची टैरिफ दरों का सामना करना पड़ा, जिससे उत्पादन लागत तेजी से बढ़ गई। कंपनियों के सामने या तो कीमतें बढ़ाने का विकल्प बचा या फिर घाटा सहकर काम करने का, और दोनों ही स्थितियां लंबे समय तक टिकाऊ साबित नहीं हुईं। औद्योगिक सेक्टर इस संकट की सबसे बड़ी मार झेलता दिख रहा है। निर्माण, विनिर्माण और परिवहन से जुड़ी कंपनियों में दिवालियापन के मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई कंपनियों ने अदालत में दाखिल अपने दस्तावेजों में साफ तौर पर लिखा है कि टैरिफ के चलते कच्चे माल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हो गई। इसके साथ ही वैश्विक सप्लाई चेन में आई रुकावटों ने समय पर सामग्री की उपलब्धता को भी प्रभावित किया, जिससे उत्पादन और डिलीवरी दोनों बाधित हुए।

इस पूरी तस्वीर को और गंभीर बनाती है अमेरिका में बनी महंगाई और ऊंची ब्याज दरों की स्थिति। फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति के चलते कर्ज लेना महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर छोटे और मझोले व्यवसायों पर पड़ा है। जिन कंपनियों ने विस्तार या रोजमर्रा के संचालन के लिए कर्ज लिया था, वे बढ़ती ब्याज दरों का बोझ नहीं झेल पा रही हैं। टैरिफ से बढ़ी लागत और महंगे कर्ज ने मिलकर कई कंपनियों को ऐसी स्थिति में धकेल दिया, जहां दिवालियापन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।

डोनाल्ड ट्रंप बार-बार यह दावा करते रहे हैं कि टैरिफ नीति से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई ताकत मिली है और देश में नौकरियां बढ़ी हैं। लेकिन संघीय आंकड़े इस दावे को कमजोर करते नजर आते हैं। नवंबर 2025 में समाप्त एक वर्ष की अवधि में अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 70 हजार से ज्यादा नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। जानकारों का कहना है कि अगर घरेलू उद्योग वास्तव में मजबूत हो रहा होता, तो रोजगार के आंकड़े इसकी पुष्टि करते, लेकिन वास्तविकता इसके उलट है।

विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर टैरिफ नीति और मौजूदा आर्थिक दबाव इसी तरह जारी रहे, तो आने वाले महीनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। कई कंपनियां पहले ही कीमतें बढ़ा चुकी हैं, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। महंगे उत्पादों के चलते मांग में गिरावट आ रही है, और इससे कंपनियों की आय और मुनाफा और घट सकता है। ऐसी स्थिति में या तो कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी करेंगी या फिर बाजार से पूरी तरह बाहर हो जाएंगी।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए यह संकट इसलिए भी अहम है क्योंकि इसका असर केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका वैश्विक अर्थव्यवस्था का बड़ा स्तंभ है और वहां के औद्योगिक व वित्तीय झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जाते हैं। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका में दिवालिया कंपनियों की संख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही, तो इसका असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश और वैश्विक सप्लाई चेन पर भी पड़ेगा।

कुल मिलाकर, 2025 में सामने आए दिवालियापन के आंकड़े ट्रंप की टैरिफ नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस नीति को अमेरिकी उद्योग और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा कवच के रूप में पेश किया गया था, वही अब कई कंपनियों के लिए बोझ बनती दिख रही है। बढ़ती महंगाई, ऊंची ब्याज दरें और व्यापारिक अनिश्चितता के बीच अमेरिकी कारोबार एक कठिन दौर से गुजर रहा है। आने वाला समय यह तय करेगा कि अमेरिका अपनी व्यापार नीति में बदलाव करता है या फिर यह आर्थिक दबाव और गहराता चला जाता है, लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि टैरिफ की मार ने अमेरिकी कंपनियों को 15 साल के सबसे बड़े संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया है।

वडोदरा मंडल के बाजवा-अहमदाबाद खंड पर स्वदेशी 'कवच' प्रणाली स्थापित की गई

(जीएनएस)। रेल परिचालन में संरक्षा को और मजबूत करने के प्रयासों के तहत, वडोदरा मंडल के सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग द्वारा 96 किलोमीटर लंबे बाजवा-अहमदाबाद खंड पर स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली 'कवच' सफलतापूर्वक स्थापित की गई है। इससे संबंधित रेल खंड पर संरक्षा में वृद्धि के साथ साथ उच्च गति पर भी सुरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित होगा। कवच प्रणाली द्वारा नए संरक्षित मार्ग पर आज 29 दिसंबर,2025 को वडोदरा - अहमदाबाद फास्ट पैसेंजर में वडोदरा के मंडल रेलवे प्रबंधक श्री राजू भडके उपस्थित रहेंगे एवं इस प्रणाली का अवलोकन करेंगे। मंडल रेल प्रबंधक श्री भडके के कुशल मार्गदर्शन में वडोदरा मंडल ने यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस खंड पर चलने वाले सभी लोकोमोटिव कवच प्रणाली से सुसज्जित हैं। इस स्वदेशी तकनीक को संरक्षा जोखिमों को स्वचालित रूप से कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो लाल सिग्नल को पार करने में रोकथाम (सिग्नल पासिंग एट डेंजर), लूप लाइनों और मुख्य रेल खंडों पर स्वचालित गति नियंत्रण, और आमने-सामने और पीछे से टक्करों से सुरक्षा जैसी कार्यक्षमताएं प्रदान करती है।

टर्मिनेटिंग / ओरिजिनेटिंग ट्रेन की सुविधा के साथ उत्राण स्टेशन का किया जा रहा है विकास, भारतीय रेल की अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों में रेल गाड़ियों की संचालन क्षमता दोगुनी करने की योजना

(जीएनएस)। यात्रा की मांग में लगातार हो रही तीव्र वृद्धि को देखते हुए, भारतीय रेल द्वारा अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों की नई रेल गाड़ियों के संचालन की क्षमता को वर्तमान स्तर से दोगुना करने की योजना है। आगामी वर्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। इस दिशा में वर्ष 2025 -26 के दौरान वडोदरा मंडल के प्रतापनगर स्टेशन पर दो नए प्लेटफार्म का निर्माण किया गया। उत्राण स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 3 एवं 4 के विस्तार के साथ अमृत भारत स्टेशन के सभी कार्य पूरे कर लिए गए है। टर्मिनेटिंग / ओरिजिनेटिंग ट्रेन की सुविधा के साथ उत्राण स्टेशन का विकास किया जाएगा, जिसमे नए हाई लेवल प्लेटफार्म का निर्माण, अप दिशा के प्लेटफार्म के विस्तार और अन्य यात्री सुविधाओं के कार्य शामिल है।

वडोदरा मंडल पर शॉर्ट टर्म यानि अगले दो वर्ष के अंतर्गत रानोली स्टेशन पर 2 पिट लाइनों एवं एक स्टेब्लिंग लाइन का निर्माण तथा उत्राण स्टेशन पर 2 नए प्लेटफार्मों का निर्माण किया जाएगा।इसके अतिरिक्त, लॉन्ग टर्म यानि 3 से 5 वर्ष की योजना के अंदर प्रतापनगर स्टेशन पर 1 पिट लाइन एवं 1 स्टेबलिंग लाइन का निर्माण प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त प्रतापनगर और उत्राण में कोचिंग क्षमता बढ़ाने के लिए कोचिंग टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा।

वर्ष 2030 तक रेल गाड़ियों की संचालन क्षमता को दोगुना करने के उद्देश्य से भारतीय रेल द्वारा अधोसंरचना विकास के महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, जिनमेनिम्न कार्य शामिल होंगे:

i. मौजूदा टर्मिनलों को अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइन, पिट लाइन और पर्याप्त शंटिंग सुविधाओं से सुसज्जित करना।

ii. शहरी क्षेत्र में और उसके आसपास नए टर्मिनलों की पहचान और निर्माण करना।

iii. मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स सहित रखरखाव सुविधाएं।

iv. विभिन्न स्थानों पर रेल गाड़ियों की बढ़ती संख्या की व्यवस्था करने के लिए यातायात सुविधा कार्यों, सिग्नलिंग उन्नयन और मल्टीट्रैकिंग के माध्यम से अनुभागीय क्षमता में वृद्धि करना।

केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस सम्बन्ध में कहा, "हम यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए विभिन्न शहरों में कोचिंग टर्मिनलों का विस्तार कर रहे हैं और अनुभागीय एवं परिचालन क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। इस कदम से हमारे रेलवे नेटवर्क का उन्नयन होगा और राष्ट्रव्यापी संपर्क सुविधा में सुधार होगा।"